भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 219

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के प्रयास

219. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विदेश नीति संबंधी पहलों के माध्यम से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और विकसित भारत बनाने में मदद मिली है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्गेरिटा)

(क) से (घ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

*****

2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के प्रयास के संबंध में श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 219 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): प्रधानमंत्री की "विकसित भारत@2047" की परिकल्पना के अनुरूप, भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें हमारे समग्र राष्ट्रीय आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास को आगे बढ़ाना और दुनिया भर में रहने और काम करने वाले भारतीयों का कल्याण और प्रगति सुनिश्चित करना शामिल है।

तदनुसार, सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विदेश नीति पहलें इस उद्देश्य के अनुरूप हैं। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने ग्लोबल साउथ और नॉर्थ में 30 से अधिक देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है और उसे सुदृढ़ बनाया है। मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी के अलावा, सरकार ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न विदेश नीति पहलें की हैं। इनमें अन्य पहलों के साथ-साथ पड़ोस प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास हेतु पारस्परिक एवं समग्र उन्नति (महासागर) पहल, हिन्द-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) और लिंक वेस्ट नीति शामिल हैं।

भारत ने विशिष्ट समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए पहल करने तथा अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं, व्यापार एवं संपर्क को बढ़ाने के लिए नए मार्ग विकसित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ प्रमुख पहलों में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) शामिल हैं।

सरकार ने मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) पर हस्ताक्षर के संबंध में भी एक सोचा-समझा दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार पहुंच के दायरे और उसकी व्यापार संपूरकताओं का विस्तार करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। 2019 से, भारत ने मॉरीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी करार (सीईसीपीए) (फरवरी 2021); भारत-यूएई सीईपीए (फरवरी 2022); भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (अप्रैल 2022) और भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार (मार्च 2024) संपन्न किया है। भारत वर्तमान में यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, श्रीलंका और ओमान के साथ एफटीए और साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत कर रहा है।

प्रौद्योगिकी साझेदारी अमेरिका, यूरोपीय संघ और फ्रांस सहित कई देशों के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन

डीसी यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने यू.एस.-इंडिया ट्रस्ट (रणनीतिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा संबंधों को बेहतर बनाना) पहल शुरू की। यूरोपीय संघ के संबंध में, अप्रैल 2022 में स्थापित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के लिए व्यापक तंत्र प्रदान करता है जिसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल शासन व्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियां तथा नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसी प्रकार, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान, सहयोग का एक प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रौद्योगिकी सहयोग था। यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित कुछ प्रमुख परिणामों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संबंधी भारत फ्रांस घोषणापत्र पर सहमति; भारत-फ्रांस डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए आशय पत्र और फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन पर 10 भारतीय स्टार्टअप की शुरुआत के लिए करार शामिल था। इसी प्रकार, हमारी अनेक राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहलों, जैसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और अटल नवाचार मिशन, के संबंध में सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न बहुपक्षीय और बहुआयामी समूहों में भागीदारी के माध्यम से, भारत अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों पर प्रभाव डालने वाले अनेक समकालीन वैश्विक मुद्दों के संबंध में भागीदार देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। इसमें संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न एजेंसियों, आईएमएफ, विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा जी20, ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड जैसे अंतर-सरकारी समूहों सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थानों में सक्रिय भागीदारी शामिल है।

इसके अलावा, भारत वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन संबंधी पहल के माध्यम से ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनकर उभरा है, जिसके तहत भारत ने तीन वर्चुअल शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की है और प्रत्येक शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक ग्लोबल साउथ देशों की भागीदारी रही। भारत का अन्य विकासशील देशों के साथ एक मजबूत विकास साझेदारी कार्यक्रम है। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने चार भागों वाले व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा जिसमें चार घटक अर्थात विकास हेतु व्यापार; सतत विकास हेतु क्षमता निर्माण; प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान; और, परियोजना विशिष्ट रियायती वित्त और अनुदान शामिल थे।

सरकार ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) सहित भारत के नेतृत्व वाली पहलों की व्यापकता को और बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हाल के महीनों में, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

हैं। इसके अलावा, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई देशों ने इंडिया स्टैक और यूपीआई सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु वैश्विक कार्यस्थल में प्रवेश हेतु निरंतर विस्तार करना है, जिसके लिए प्रमुख पहलें की गई हैं, जिसमें भुवनेश्वर और नागपुर में चल रही ई-पासपोर्ट पायलट परियोजनाएं, ई-माइग्रेट मोबाइल एप्लीकेशन का संचालन, जो क्रियाशील है और सरकारी ऐप स्टोर तथा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है; तथा विभिन्न देशों के साथ आवाजाही करार पर हस्ताक्षर किया जाना शामिल है।

भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, सरकार ने हाल के महीनों में अल्बानिया, गैबॉन, जॉर्जिया, लातविया, तिमोर-लेस्ते में नए भारतीय दूतावासों तथा मार्सिले, मैनचेस्टर, बेलफास्ट, ब्रिस्बेन, ऑकलैंड और बार्सिलोना में नए भारतीय कोंसलावास की स्थापना द्वारा मंत्रालय की संस्थागत क्षमता और राजनयिक सामर्थ्य को मजबूत किया है।

मंत्रालय ने निवेश को आकर्षित करने के संबंध में राज्य सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच में सहायता प्रदान की है और उसे सुविधाजनक बनाया है। हमारे राजनयिक मिशनों ने हमारे राज्यों द्वारा पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा देने में भी सुविधा प्रदान की है।

इन विदेश नीति पहलों का उद्देश्य भारत की द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय राजनयिक पहुंच तथा मित्रवत देशों के साथ विकास साझेदारी को मजबूत करना है, और साथ ही भारत के रणनीतिक हितों एवं विकास प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना है ताकि "विकसित भारत@2047" के दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

*****